

Part- II  
(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)  
State serial No. of proposal

7. Location of the project/Scheme

7	(i)	State/Union Territory	Rajasthan
	(ii)	District.	Jodhpur
	(iii)	Forest Division	Jodhpur
	(iv)	Area of forest land proposed for diversion (in ha.)	7.534 hact
	(v)	Legal status of forest	PF
	(vi)	Density of vegetation	0.01
	(vii)	Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of tree (to be enclosed. in case of irrigation/ gydel projects enumeration at FRL, FRL-2 meter & FRL 4 meter also to be enclosed.)	Attached
	(viii)	Brief note on vulnerability of the forest area to erosion.	Rocky area
	(ix)	Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest.	Inside Forest Area
	(x)	Whether forms part of National park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve elephant corridor, ec. (If so, the details of the area and comments of the chief Wildlife Warden to be annexed)	No
	(xi)	Whether any rare/ endangered / unique species of flora and fauna found in the area-if so details thereof.	No
	(xii)	Whether any protected archaeological / heritage site/ defence establishment or any other important monument is located in or near the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.	No
8		Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 of part-I is unavoidable and barest minimum for the project. if no recommended area item- wise with details of alternatives examined.	Yes
9.		Whether any work in violation of the Act has been carried out (yes/no). If yes details of the same including period of work done, action taken on erring officials. Whether work in violation is still in progress.	No.

उप वन संरक्षक  
जोधपुर



10.	Details of compensatory afforestation scheme	CA Model As Per GOR Order No. 13.11.2017
	(i) Details of non forest area/ degraded forest area identified for compensatory afforestation its distance from adjoining fores, number of patches, size of each pathch	DFA identified
	(ii) Map showing non-forest/ degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries.	Attached
	(iii) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted implementing agency, time schedule, cost structure, etc	Attached Species to be planted ( Khejri, Neem, A Tortalis Kumtha etc.)
	(iv) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme.	Attached
	(v) Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view. (To e signed by the concerned Deputy Conservator of Forests)	Attached
11.	Site inspection report of the DCF (to be enclosed) expecially highlighting facts asked in col. 7(xi, xii), 8 and 9 above.	Attached
12	Division/District Profile	
	(i) Geographical area of the district	Jodhpur District Area 20850 sq. km.
	(ii) Forest area of the district.	237.06 sq. km.
	(iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases.	194.52 ha. in 18 cases
	(iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on	
	a forest land including penal comensatory afforestation,	308.82 ha.
	b Non-forest land	29.65 ha
13	Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.	जोधपुर रिंग रोड सड़क मार्ग निर्माण हेतु आवेदित क्षेत्र का संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। आवेदित 7.534 हैक्टर क्षेत्र मौजा गँवा के खसरा नं. 858, 867 एवं 884 में आता है एवं वर्तमान में यह क्षेत्र वन खण्ड बड़ाभाखर का अंग है। इस सड़क मार्ग निर्माण हेतु अतिरिक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण वनभूमि को न्यूनतम सीमा तक प्रयोग में लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस सड़क निर्माण के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष डी.बी. रिट कन्टैम्प्ट सं. 371/2016 जनहित याचिका भी विचाराधीन हैं। मा.न्याया. ने आदेश दिनांक 24.09.2018 में, आदेश

7-  
जोधपुर



		<p>प्रदान किया गया है कि NHAI द्वारा रिंग रोड निर्माण हेतु आवश्यक 7.534 हैक्टर का, वन विभाग को चार सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये गये। मा. न्याया के आदेशों की अनुपालना में प्रकरण वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु तथा स्थानीय आवश्यकताओं, लोक महत्व एवं राष्ट्रीय हित में इस प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वन विभाग एवं यूजर एजेन्सी के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण के दौरान मौजा बड़ली के मीन खसरा नं. 534 की लगभग 1.33 हैक्टर, उक्त प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त भूमि भी प्रस्तावित रिंग रोड के चौड़ाईकरण में आयेगी। इस मीन खसरा नं. 534 में वन विभाग की 101.22 हैक्टर, पी.डब्ल्यू. डी. की 0.308 हैक्टर, जे.डी.ए. की 2.44 हैक्टर एवं खनिज विभाग की 5.26 हैक्टर कुल 109.22 हैक्टर भूमि है। इन चारों खातेदारान के मध्य तरमीम नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सड़क मार्ग की सीमा में अतिरिक्त रूप से आने वाली भूमि किस विभाग की है। संयुक्त निरीक्षण (वन विभाग एवं NHAI) द्वारा पाया गया कि सड़क मार्ग निर्माण के लिए लगभग 1.33 हैक्टर भूमि की खसरा नं. 534 में आवश्यकता है जबकि वास्तव में पी. डब्ल्यू. डी. के नाम 0.308 हैक्टर भूमि ही दर्ज है एवं सड़क निर्माण हेतु लगभग 1.02 हैक्टर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। इस कार्यालय के पत्रांक 9312 दिनांक 27.09.2018 एवं 9452 दिनांक 03.10.2018 (संलग्न) से यूजर एजेन्सी को अवगत करवा दिया गया है परन्तु यूजर एजेन्सी से आज दिनांक तक प्रत्युत्तर शेष है। अतः तरमीम के बाद सड़क मार्ग की सीमा में अतिरिक्त रूप से आने वाली भूमि वनविभाग की भूमि पायी जाती है तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अतिरिक्त वनभूमि के संबंध में भारत सरकार से प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के जरिए अनुमति प्राप्त करनी होगी इसी शर्त के साथ में इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।</p>
--	--	---

signature

Name: Narendra singh shekhawat

**नरेंद्र सिंह शेखावत**

official Seal

Date : 12.10.18

Place : Jodhpur